

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या 180/2013/बीकानेर
3. अपील संख्या 182/2013/बीकानेर
5. अपील संख्या 184/2013/बीकानेर

मैसर्स महेश एजेन्सीज,
गोलच्छा चौक, बीकानेर।

बनाम्

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर।

7. अपील संख्या 880/2013/बीकानेर
9. अपील संख्या 882/2013/बीकानेर
11. अपील संख्या 884/2013/बीकानेर

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बीकानेर।

बनाम्

मैसर्स महेश एजेन्सीज,
गोलच्छा चौक, बीकानेर।

2. अपील संख्या 181/2013/बीकानेर
4. अपील संख्या 183/2013/बीकानेर
6. अपील संख्या 185/2013/बीकानेर

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

8. अपील संख्या 881/2013/बीकानेर
10. अपील संख्या 883/2013/बीकानेर
12. अपील संख्या 885/2013/बीकानेर

.....अपीलार्थी.

.....प्रत्यर्थी

खण्डपीठ

श्री वी.श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के.एल.जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी.के.पारीक अभिभाषक

श्री अनिल पोखरणा, उपराजकीय अभिभाषक

.....व्यवहारी फर्म की ओर से.

.....राजस्व विभाग की ओर से.

निर्णय दिनांक : 05.10.2017

निर्णय

1. अपीलार्थीगण व्यवहारी/राजस्व द्वारा यह अपीलें उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, बीकानेर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा निम्न तालिकानुसार पारित आदेशों के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, बीकानेर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्द्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 25, 55 एवं 61 के अन्तर्गत पारित आदेशों के जरिये सृजित मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने/अस्वीकार किये जाने को विवादित किया है।

कर बोर्ड की अपील संख्या	अपीलीय आदेश सं. एवं दिनांक	क.नि.आ. दिनांक	क.नि.वर्ष	आरोपित (राशि ₹ में)		
				अन्तर कर	ब्याज	शास्ति
180/2013	357/22.01.13	02.07.2012	2010-11	1,62,224	34,067	
181/2013	360/22.01.13	02.07.2012	2006-07	1,42,208	98,124	
182/2013	359/22.01.13	02.07.2012	2007-08	1,37,057	78,123	
183/2013	356/22.01.13	02.07.2012	2011-12	23256	33712	
184/2013	358/22.01.13	02.07.2012	2009-10	2,16,568	71,467	
185/2013	355/22.01.13	02.07.2012	2008-09	1,42,316	64,042	
880/2013	360/22.01.13	02.07.2012	2006-07			2,84,416
881/2013	359/22.01.13	02.07.2012	2007-08			2,74,114
882/2013	355/22.01.13	02.07.2012	2008-09			2,84,632
883/2013	358/22.01.13	02.07.2012	2009-10			4,33,136
884/2013	357/22.01.13	02.07.2012	2010-11			3,24,448
885/2013	356/22.01.13	02.07.2012	2011-12			75,292

लगातार.....2

2. समस्त प्रकरणों के तथ्य समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है, निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक से रखी जावें।
3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, वृत्त-ए, बीकानेर (जिसे आगे "जॉच अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण किये जाने पर उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं रिकॉर्ड की जांच पर पाया गया कि व्यवहारी द्वारा मैसर्स गोदरेज हरसे लिमिटेड द्वारा निर्मित कन्फैक्शनरी पर 4 प्रतिशत कर वसूल किया जा रहा है, जबकि व्यवहारी कम्पनी द्वारा Natrine, Maha Lacto, Aamras, Gulkand, Koka Naka, Lolipops आदि ब्रांडेड कन्फैक्शनरी बेची जा रही है, जिन पर वैट की दर 12.5/14 प्रतिशत देय है।
4. व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे उत्पादन के नमूने लिये गये तथा आलौच्य अवधियों से बिक्री की गयी Natrine, Maha Lacto, Aamras, Gulkand, Koka Naka, Lolipops की बिक्री का विवरण प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये गये एवं आलौच्य अवधियों में माल ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी की श्रेणी में आने तथा वैट अनुसूची-चतुर्थ के तहत करयोग्य नहीं होने तथा वैट अनुसूची-पंचम के तहत सामान्य कर दर 14 प्रतिशत से करयोग्य होना मानते हुये व्यवहारी द्वारा किये गये कृत्य को करापवंचन की श्रेणी में पाया तथा 9 प्रतिशत अन्तर कर संग्रहित/जमा कराया जाना नहीं पाया, जिसके फलस्वरूप सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने 'Prosecutor should not be judge' की अवधारणा के तहत पत्रावली कर निर्धारण अधिकारी को स्थानान्तरित कर दी।
5. कर निर्धारण अधिकारी ने पत्रावली, उपलब्ध रिकॉर्ड व प्रोडक्ट्स के रेपर्स का अवलोकन किया जिसमें पाया कि व्यवहारी द्वारा विक्रय किये जा रहे प्रोडक्ट्स Natrine, Maha Lacto, Aamras, Gulkand, Koka Naka, Lolipops के Indredients को देखने पर यह माल Sugar Candy made of Sugar & Glucose नहीं पाया। रेपर्स के अवलोकन से Natrine, Maha Lacto, Aamras, Gulkand, Koka Naka, Lolipops पर SUGAR BOILED CONFECTIONERY व R अंकित पाया गया जिससे यह स्पष्ट है कि यह ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी है क्योंकि ऐसा ही Eclairs पर अंकित पाया गया। Maha Choco पर Maha Creamy Chocolaty भी अंकित है, जिससे भी स्पष्ट है कि इसमें चोकलेट है जिसे अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 में Exclude किया गया है। व्यवहारी के विवादित उत्पाद 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' प्रविष्टि संख्या 163 अनुसूची-चतुर्थ के तहत करयोग्य नहीं पाये गये। व्यवहारी ने ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी का आलौच्य अवधियों में की गई बिक्री (Eclairs) के अतिरिक्त किया है तथा Sugar Candy made of sugar मानकर 5 प्रतिशत से कर संग्रहित किया है, जबकि ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 से पृथक की गयी है, जिसके फलस्वरूप यह अनुसूची-पंचम के तहत आलौच्य अवधि में 14 प्रतिशत से करयोग्य माल होने के कारण व्यवहारी के द्वारा गलत निर्वचन किया तथा बिक्री विवरणियों में कर दर की गलत घोषणा करके 9 प्रतिशत से राजकोष में कम कर अदा करते हुए परिवर्जन व अपवंचन किया जाना प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी को अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत नोटिस जारी किये एवं प्रस्तुत जवाब से असंतुष्ट होते हुये उपरोक्त तालिकानुसार मांगे सृजित की, उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलें अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनको शास्ति के बिन्दु पर स्वीकारते हुये कर व ब्याज के बिन्दु पर अस्वीकार किया गया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी एवं विभाग द्वारा उक्त अपीलें/क्रास ऑब्जेक्शन अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष पेश की गई है।
6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई।

7. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने निवेदन किया कि उनके द्वारा किया गया उत्पाद वैट अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' के तहत आता है तथा उसी के अनुसार व्यवहारी की ओर से कर संग्रहित करते हुए राजकोष में जमा कराया जा रहा है। विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अधिनियम लागू होने के समय अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 154 'Confectionery excluding chocolate' थी, जो दिनांक 08.05.2006 की अधिसूचना से संशोधित होकर Excluding branded Confectionery हुआ तथा दिनांक 01.06.2006 से नई प्रविष्टि संख्या 163 आयी 'Sugar Candy made of sugar and glucose but excluding coco' जिसके अनुसार कुछ उत्पाद इस श्रेणी के होने के कारण तदनुसार कर संग्रहित करके जमा कराया गया। अनुसूची-चतुर्थ की प्रविष्टि संख्या 163 में All type of sugar candy सम्मिलित है तथा 'Coco' से निर्मित केण्डी इसमें सम्मिलित नहीं है। विधायिका ने Sugar Candies made of Sugar and glucose and containing Flavours, Creams and colors को स्पष्टतः पृथक् नहीं किया है। विद्वान अभिभाषक ने लेब रिपोर्ट दर्शाते हुये कथन किया कि इसके उत्पाद में 90 प्रतिशत से अधिक शुगर है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय Gurudev dutta Vksss Margyadit and others Vs. State of Maharashtra and others 2001 (004) SSC - 0534(SC) का दृष्टान्त उद्धरित किया। साथ ही उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी के उत्पाद प्राथमिक रूप में Sugar & Glucose से बने हैं तथा नाम मात्र के Flavouring Substances, Emulsifiers and colorants होते हैं। विद्वान अभिभाषक ने सीटीओ बनाम हीरा लाल मुरलीधर, 1993 टैक्स वर्ल्ड 32 सैक्शन-1 में मीठी गोली जिसमें 90 प्रतिशत शुगर को कन्फैक्शनरी नहीं, बल्कि शुगरकेण्डी माना है। विद्वान अभिभाषक ने अतिरिक्त आयुक्त का धारा 12-ए आरएसटी एक्ट का आदेश दिनांक 02.01.1989 मैसर्स अशोक एन्टरप्राइजेज कोटा का दृष्टान्त देते हुए Lozenges Toffee को मीठी गोली माना जाना एवं विभाग पर बाध्यकारी होना बतलाया है। उन्होंने कतिपय लैबोरेट्री की जांच रिपोर्ट भी प्रस्तुत की।

अपने तर्कों के समर्थन में इनके द्वारा निम्नलिखित न्यायिक व्यवस्थाएँ प्रस्तुत की गईं:-

1. [Supreme Court of India] Frick India Limited Vs State of Haryana May 13, 1994.
2. [In The Supreme Court of India] (2009) VST 249 (SC) Sree Krishna Electricals Vs State of Tamil Nadu April 21, 2009
3. [Supreme Court of India] J.K. Synthetics Ltd. Vs Comm. Taxes Officer (C.A. Nos. 3414 to 3416 of 1982) Birla Cement Works Vs State of Rajasthan May 9, 1994.
4. [2012] 51 VST 130(Mad) [In The High Court] Cadbury India Limited Vs Assistant Commissioner (CT), Chennai July, 2009
5. [In The High Court of Karnataka At Bangalore] Kundanamal Ganeshmal And Borthers Vs State of Karnataka February 12, 1993.
6. [2012] 48 VST 107 (AP) [In The Andhra Pradesh High Court] Banyan Enterprises Vs Commercial Tax Officer August 24, 2011.
7. [2017] 98 VST 172 (Bom.) [In The Bombay High Court] Zamil Steel Buildings India Pvt. Ltd. Vs State of Maharashtra December 23, 2016
8. [In The High Court of Rajasthan At Jodhpur] Black Stone Rubber Industries Pvt. Ltd. Vs State of Rajasthan February 19, 2001.
9. [2011] 39 VST 184(All) [In The Allahabad High Court] Kesar Enterprises Ltd. Vs State of U.P. August 27, 2010/
10. [2011] 43 VST 222(All) [In The Allahabad High Court] Dabur India Limited Vs State of U.P. December 6, 2010/
11. [In The Allahabad High Court] Harbans Lal Malhotra Vs Assistant Commissioner Ghaziabad July 28, 1994
12. [In The High Court of Kerala At Ernakulam] New Prasanthi Automobiles Co. Vs State of Kerala September 26, 1992.

13. Reportes of Sales Tax Cases Vol. 146 2006 [High Court of Madhya Pradesh] Commissioner of Commercial Tax, Indore Vs Modern Agency October 25, 2004.
14. [In The High court of Rajasthan] Jaipur Bench Cycle Hatt of Jaipur Vs The Board of Revenue May, 13, 1977.
15. [2007] 5 VST 197 (All) [In The Allahabad High Court] Carbon Crafts Pvt. Ltd. Vs state of U.P. December 13, 2005.
16. In The High Court of Judicature for Rajasthan at Jodhpur Commercial Taxes Officer Vs Ms Heera Lal Murlidhar Bikaner Date July 2, 1992.

अतः उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों एवं क्रास आब्जेक्शन को स्वीकारते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

8. राजस्व की ओर से विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि हाल ही में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.02.2017 मैसर्स परफेटी वैन मेली इण्डिया प्रा.लि. बनाम सरकार प्रकरण संख्या 473/2011 एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय ने समान तथ्यों पर आधारित प्रकरणों में ब्राण्डेड कन्फेशनरी की बिक्री पर सामान्य कर दर निर्धारित की है एवं आरोपित ब्याज को बहाल किया है। साथ ही माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम सरकार (2009) 23 VST 249 (SC) के परिप्रेक्ष्य में आरोपित शास्ति को अपास्त किया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में पारित निर्णय इन प्रकरणों पर आच्छादित बतलाते हुये उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया है।

9. उभयपक्षीय बहस सुनी गई तथा उपलब्ध रेकार्ड एवं प्रस्तुत न्यायिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में मुख्य विवादित बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा निर्मित Natrine, Maha Lacto, Aamras, Gulkand, Koka Naka, Lolipops की बिक्री राज्य में की गई है। कर निर्धारण अधिकारी ने जाँच में यह भी पाया कि इसके निर्माण हेतु Sugar, Liquid Glucose, Condensed Sweetened Milk (16.9%) Butter(Fat), Vegetable Oil, edible common Salt, malt extract, Colours, Flavor, antioxidants, Acidity regulators आदि ingredients का उपयोग किया गया है जिनकी ब्लेंडिंग (Confection) से ये कन्फैक्शनरी तैयार की गयी है एवं इन सभी उत्पादों के रजिस्टर्ड ट्रेड मार्क प्राप्त किये गये हैं। सशक्त अधिकारी ने लेखा पुस्तकों की जांच पर पाया कि व्यवहारी द्वारा ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी का विक्रय किया गया है।

10. व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधियों में बिक्रीत माल अधिनियम की अनुसूची-IV की प्रविष्टि संख्या 163 "Sugar Candy made of sugar & Glucose but excluding coco" के अनुसार 5 प्रतिशत करदेयता का माल नहीं होकर Sugar and Glucose के अलावा अन्य खाद्य सामग्री की Mixing and Blending सिस्टम से निर्मित उत्पाद की बिक्री होने पर व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल Sugar Candy नहीं होकर ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी होना सिद्ध होता है। निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में समस्त तथ्यों को विस्तृत रूप से विवेचित करते हुये व्यवहारी द्वारा की गई विवादित बिक्री को ब्राण्डेड कन्फैक्शनरी प्रोडक्ट की ही बिक्री निर्धारित की गई है एवं अधिनियम की अनुसूची-V के तहत निर्धारित सामान्य दर से करदेयता निर्धारित करते हुये व्यवहारी के विरुद्ध आलौच्य अवधियों में उपरोक्त तालिकानुसार करारोपण किया है, वह विधिनुकूल है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने समान तथ्यों पर विवादित कन्फैक्शनरी पर एसबी एसटीआर/रेफरेंस संख्या 473/2011 मैसर्स परफेटी वैन मेली इण्डिया प्रा0लि0, जयपुर व अन्य बनाम उपायुक्त (अपील्स) तृतीय, व अन्य निर्णय दिनांक 17.02.2017 में दिये गये निर्णायक निर्णय में सुस्थापित किया है कि :-

"In my view, applying the common parlance test which has been held appropriate by the Apex court time and again in matters like this, the

products in which the assessee are dealing, are certainly branded toffees. Taking into consideration the aforesaid reasoning of the Apex court as well as by this court (supra), in my view the finding reached by all the three authorities in unison is well reasoned and no interference is required to be taken into consideration and accordingly while the tax is upheld and consequently the interest being consequential, is also upheld."

माननीय न्यायालय का उपरोक्त निर्णय अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा बिक्रीत माल/समान प्रकृति के माल की बिक्री के सम्बन्ध में ही है, जिसके हस्तगत प्रकरण में पूर्णतः लागू होने से कर व ब्याज के बिन्दु पर कर निर्धारण एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

11. जहां तक शास्ति का प्रश्न है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 21.04.2009 प्रकरण श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तमिलनाडू व अन्य (2009) 23 VST 249 (SC) का शास्ति के संबंध में निर्णायक अंश निम्न प्रकार है :-

"So far as the question of penalty is concerned the items which were not included in the turnover were found incorporated in the appellants account books. Where certain items which are not included in the turnover are disclosed in the dealer's own account books and the assessing authorities includes these items in the dealers turnover disallowing the exemption penalty cannot be imposed. The penalty levied stands aside."

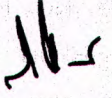
चूंकि उक्त प्रकरण वस्तुओं के वर्गीकरण से सम्बन्धित था, जो शुरू से ही विवादित किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक से जबकि अपीलार्थी व्यवहारी ने समस्त बिक्री विवरणियों में दर्शायी है, आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी ने अपास्त कर कोई त्रुटि कारित नहीं की गई है, तथा माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में भी शास्ति को अपास्त करना विधिक माना है। तदनुरूप इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

12. उपरोक्तानुसार अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेशों में किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, अतः अपीलीय अधिकारी के आदेशों को यथावत रखते हुये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलें व क्रॉस आब्जेक्शनों को अस्वीकार किया जाता है, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय के परिप्रेक्ष्य में विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार की जाती है।

13. परिणामस्वरूप व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलें/क्रॉस आब्जेक्शन तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत ~~अपीलें~~ अपीलें अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(के.एल.जैन)
सदस्य


(वी.श्रीनिवास)
अध्यक्ष